आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए समय पर मसौदा तैयार किया है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

31 मई, 2019

"गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आरबीआई के प्रारूप मानदंड समय पर।"

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो पहले से ही एक गंभीर तरलता संकट का सामना कर रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नए नियामक मानदंडों के कारण कई नई चुनौतियों का सामना करेंगी। केंद्रीय बैंक ने जमा लेने और गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन पर मसौदा मानदंडों को जारी किया है।

इन प्रस्तावित नियमों के अनुसार, एनबीएफसी को एक उच्च तरलता कवरेज अनुपात (LCR) का अनुपालन करना होगा, जो कि एनबीएफसी को उच्च-गुणवत्ता की तरल संपत्ति के रूप में रखने की आवश्यकता वाली परिसंपत्तियों का अनुपात है, जिसे जल्दी और आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। नए मानदंड, जिसकी संभावना है कि आरबीआई द्वारा अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले चार वर्षों में लागू किए जाएंगे, एनबीएफसी के मार्जिन पर महत्वपूर्ण दबाव डालेंगे।

इन मानदंडों के तहत, NBFC को अपने LCR को शुरू में 60% नेट कैश आउटफ्लो पर बनाए रखना होगा और अप्रैल, 2024 तक इसे 100% तक सुधारना होगा। यदि मानदंडों को लागू किया जाता है, तो NBFC को अपने पैसे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कम जोखिम वाली तरल संपत्ति,जैसे कि सरकारी बॉन्ड, जो उच्च-जोखिम वाली अवैध संपत्ति की तुलना में बहुत कम रिटर्न देते हैं,में रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वर्तमान संकट के संदर्भ में सख्त मानदंडों को देखा जाना चाहिए, जहाँ प्रमुख एनबीएफसी विभिन्न उधारदाताओं के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

एनबीएफसी,जो लंबी अवधि के लिए ऋण देने और अल्पावधि के लिए उधार लेने के व्यवसाय में हैं,आमतौर पर अपनी संपत्ति और देनदारियों की अवधि में समस्या होने के कारण अपने उधारकर्ताओं को समय पर वापस भुगतान करने में असमर्थ होने का जोखिम उठाती हैं। यह विशेष रूप से ऐसे उदाहरणों में है जहाँ अल्पकालिक उधारदाताओं के बीच घबराहट होती है, जैसा कि पिछले साल हुआ था जब उधारदाताओं ने अपनी पूंजी की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर, वापस पूर्ण भुगतान करने की मांग की थी।

दूसरे शब्दों में, एनबीएफसी किसी भी प्रकार के तरलता संकट से बचने के लिए अपने ऋणों में विफल रहे अल्पकालिक ऋणदाताओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। नए मानदंड एनबीएफसी को आवश्यक बफर पूंजी के बिना दीर्घकालिक ऋण का विस्तार करने के लिए अल्पावधि में उधार लेने से हतोत्साहित करेंगे। यह एनबीएफसी को उनके उधार के दायरे को कम करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन यह उन्हें बड़े संकटों से बचाएगा और अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कदम उठाने के लिए सरकार या आरबीआई की आवश्यकता को कम करेगा।

निस्संदेह, एनबीएफसी ने हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हिस्सा लेकर क्रेडिट को व्यापक और गहन बनाने में एक जबरदस्त काम किया है, जो कि बैड लोन जैसे संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालांकि, NBFC के लिए नवीनतम तरलता मानदंड की प्रणालीगत संकटों को दूर करने के लिए आवश्यकता है।

जोखिम प्रबंधन मसौदा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आरबीआई ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक संपत्ति के आकार वाली सभी गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सभी डिपॉजिट लेने वाले NBFC को अपनी संपत्ति के आकार के बावजूद, तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के संदर्भ में एक तरलता बफर बनाए रखना है।
- एनबीएफसी और मूल निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर एक मसौदे में, ये उपाय संभावित तरलता अवरोधों के लिए एनबीएफसी के लचीलापन को बढ़ावा देंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तरलता तनाव से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) है।
- बैंकिंग नियामक ने प्रस्तावित किया कि यह 01 अप्रैल, 2020 से 01 अप्रैल, 2024 तक LCR को एक ग्लाइड पथ के माध्यम से लागू करेगा।

क्या है रेपो रेट?

- बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए अक्सर ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज्यादा नहीं होती।
- इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए (ओवरनाइट) कर्ज लेना।
- इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं।
- रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके।
- रेपो दर में बढ़ोत्तरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा।

क्या है रिवर्स रेपो रेट?

- रिवर्स रेपो रेट ऊपर बताए गए रेपो रेट से विपरीत होती है। बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है।
- बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
- अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा नकदी है, तो वह रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोत्तरी कर देता है, जिससे बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना धन रिजर्व बैंक के पास रखने को प्रोत्साहित होते हैं और इस तरह उनके पास बाजार में छोड़ने के लिए कम धन बचता है।

सीआरआर

- देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है।
- इसे ही कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) या नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं।

एसएलआर

- जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं, उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
- कॉमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन-देन को पूरा करने में किया जाता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. रेपो रेट में बढ़ोत्तरी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है।
2. आरबीआई बगैर ब्याज दर में बदलाव किए नकदी की तरलता को कम करने के लिए एस.एल.आर. में बढ़ोत्तरी कर देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. बाजार में नकदी की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए आर.बी.आई. निम्नलिखित में से किस दर मे बढ़ोत्तरी कर देता है?

(a) रेपो दर
(b) रिवर्स रेपो दर
(c) सीआरआर
(d) एसएलआर

Q. Consider the following statements:

1. With the increase in repo rate, it is cheaper to take loans from the Reserve Bank for banks.
2. Without changing the interest rates, RBI increases the SLR to reduce liquidity.

Which of the statement above is/are true?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Q. To control the excess of cash in the market, RBI increases which of the following rates?

(a) Repo rate
(b) Reverse repo rate
(c) CRR
(d) SLR

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- हाल ही में आरबीआई द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी नया मसौदा वर्तमान प्रणालीगत संकट से उबरने में किस प्रकार सहायक होगा? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. How recently will the new draft released by the RBI for non-banking financial companies be helpful in recovering from the current systemic crisis? Discuss. (250Words)

नोट : 30 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b) होगा।